

प्रेषक,

डी०एस० गर्बाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अर्द्ध कुम्भ मेला-2016,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 20 नवम्बर, 2015

विषय—अर्द्ध कुम्भ मेला-2016 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नीलधारा सैक्टर में अस्थाई विद्युत आपूर्ति कार्य।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1008/अ०कु०मे०/विद्युत वि०/नीलधारा सै०अ० कार्य, दिनांक 16.10.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्द्ध कुम्भ मेला-2016 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नीलधारा सैक्टर में अस्थाई विद्युत आपूर्ति कार्य के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रु० 220.13 लाख के सापेक्ष टी०ए०सी० परीक्षण के उपरान्त रु० 220.13 लाख (रु० दो करोड़ बीस लाख तेरह हजार मात्र) के कार्य पर अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रु० 100 लाख (रु० एक करोड़ मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (i) भारत सरकार से प्राप्त धनराशि की प्रथम किश्त से ही उक्त धनराशि का समायोजन सुनिश्चित करेंगे।
- (ii) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
- (iii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (iv) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि की स्वीकृति गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

40

- (v) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
- (vi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
- (vii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (viii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
- (ix) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व करा लिया गया है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय व कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाय।
- (x) निर्माण कार्य का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।
- (xi) आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
- (xii) अस्वीकृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी। साथ ही यह परिवर्तन स्वीकृत धनराशि की सीमान्तर्गत ही किया जाएगा।
- (xiii) प्रश्नगत कार्य का गहन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण ऊर्जा विभाग द्वारा भी किया जाएगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, वित्तीय हस्त पुस्तिका व बजट मैनुअल के अनुसार किया जाय।

4- इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना-0109-हरिद्वार अर्द्ध कुम्भ मेला, 2016 हेतु अवस्थापना सुविधा की मानक मद संख्या-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-793/XXVII(2)/2015, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

6- एलॉटमेंट आई0डी0 संख्या-एस01511130129 एवं एच01511130773 दिनांक 20 नवम्बर, 2015 के द्वारा उक्त धनराशि ऑनलाइन रूप से अवमुक्त की गई है।

भवदीय,


(डी0एस0 गब्याल)
सचिव।

संख्या-1882(1)/IV-3/2015-04(104)/2015, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0-1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
6. मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता, (वितरण) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन हरिद्वार।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. अधीक्षण अभियन्ता, पावर कारपोरेशन, हरिद्वार।
11. अधिशासी अभियन्ता, पावर कारपोरेशन, हरिद्वार।
12. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
13. वित्त अनुभाग-2
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(रईस अहमद)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Urban Development (S054)

आवंटन पत्र संख्या - 1882/15-04(104)2015

अनुदान संख्या - 013

असॉटमेंट आई डी - S1511130129

आवंटन पत्र दिनांक -20-Nov-2015

HOD Name - Secretary, Urban Development (Grants) (9005)

- 1: लेखा शीर्षक 2217 - शहरी विकास 03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
800 - अन्य व्यय 01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिष्ठानित योज
09 - हरिद्वार अर्द्धकुम्भ मेला 2016 हेतु अवस्थापना सुविधा

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Plan Voted
			योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	350340000	10000000	360340000
	350340000	10000000	360340000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 10000000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Urban Development (Grants) (9005)

आवंटन पत्र संख्या - 1882/15-04(104)2015

अनुदान संख्या - 013

अलोटमेंट आई डी - H1511130773

आवंटन पत्र दिनांक - 20-Nov-2015


DDO Name - Meladhikari KumbhHaridwar (2871) . Treasury - Haridwar (6500)

- 1: लेखा शीर्षक 2217 - शहरी विकास 03 - छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
800 - अन्य व्यय 01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिश्चानित योजना
09 - हरिद्वार अर्द्धकुम्भ मेला 2016 हेतु अवस्थापना सुविधा

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Plan Voted
			योग
20 - सहायक अनुदान/अनुदान/राज	330340000	10000000	340340000
	330340000	10000000	340340000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

10000000


(निर्वाह अधिकारी)
पत्र सचिव,
आवास विकास विभाग
(आवास विकास विभाग)